सत्यमेव जयते

# सप्तदश

# बिहार विधान सभा

## चतुर्थ सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

### वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 09 अग्रहायण, 1943 (श०) / 30 नवम्बर, 2021 (ई०)

**प्रश्नों की कुल संख्या 08**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | शिक्षा विभाग .. .. .. .. | 06 |
| (2) | समाज कल्याण विभाग .. .. .. .. | 01 |
| (3) | परिवहन विभाग .. .. .. .. | 01 |
| | कुल योग -- | 08 |

शिक्षकों का नियोजन

1. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 8000 हजार शिक्षकों को नियोजन हेतु दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को मंत्रिपरिषद् के निर्णय एवं वित्त विभाग के पत्रांक 7/नि01-08/2011-1141, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के द्वारा स्वीकृति के उपरान्त अभीतक नियोजन संबंधी कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

--------

आच्छादित करना

2. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में निबंधित आँकड़ों के अनुसार अप्रील, 2020 से लेकर 5 जून, 2021 तक बिहार के 308 बच्चे माता और पिता दोनों को ही खोकर अनाथ हो गये ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुये बच्चों के लिये बाल सहायता योजना के तहत 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है परन्तु अनाथ हुये 308 बच्चों को आजतक कोई सहायता नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अनाथ हुये बच्चों को अभीतक बाल सहायता योजना से आच्छादित नहीं किये जाने का औचित्य क्या है ?

--------

बी0 एच0 सीरीज का नम्बर प्लेट

3. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मोटर वेहिकल ऐक्ट, 1988 पूरे देश के लिये बाध्यकारी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को सुगम बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा मोटर वेहिकल ऐक्ट, 1988 के सेक्शन-47 में संशोधन कर बी0 एच0 सिरीज नम्बर प्लेट दिये जाने की कार्रवाई दिनांक 15 सितम्बर, 2021 से प्रारंभ की गयी है परंतु बिहार में अभीतक बी0 एच0 सिरीज नम्बर प्लेट जारी नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार राज्य में भी बी0 एच0 सिरीज का नम्बर प्लेट जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

4. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''विश्वविद्यालय में किताबों की खरीद का खेल'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में किताबों की खरीददारी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है जिसमें ताजा संस्करण की बजाय पुरानी किताबों को बिना टेंडर के खरीदी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिना भवन वाले विश्वविद्यालय ने भी 5 करोड़ की किताबें बिना सिलेबस के अनुरूप खरीदी है तथा रख-रखाव के लिये 50 लाख सलाना किराये पर एक-एक फ्लोर ले लिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

निःशुल्क फॉर्म भरवाना

5. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2022 में मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये 17 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 नवम्बर तक मात्र 13 लाख विद्यार्थियों ने ही फॉर्म भरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोरोना के कारण उत्पन्न पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण ही 4 लाख विद्यार्थियों द्वारा मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आर्थिक तंगी के कारण फॉर्म नहीं भरने वाले सभी 4 लाख विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि का विस्तार करते हुये उनसे निःशुल्क फॉर्म भरवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य

6. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक व इंटर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिये जाने का प्रावधान है जिसके तहत अधिकतम चार लाख रुपये तक का लोन विद्यार्थी ले सकते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु मात्र 23 हजार विद्यार्थियों को ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक लाख के लक्ष्य को घटाकर 75 हजार कर दिया गया है जबकि 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य कम करने तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्धि कम रहने का औचित्य क्या है ?

--------

ट्यूशन के प्रति आकर्षण

7. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 22 नवम्बर, 2021 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''बिहार व बंगाल में सबसे अधिक ट्यूशन पढ़ते हैं स्कूली बच्चे'' के समाचार को ध्यान में रखकर क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ए0एस0ई0आर0 2021 ई0 के राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2021 ई0 में पूरे देश में 40 प्रतिशत विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे ट्यूशन लेते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में उक्त रिपोर्ट के अनुसार 2021 ई0 में 73.5 प्रतिशत बच्चे ट्यूशन लेते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में ट्यूशन के प्रति आकर्षण को कम करके राष्ट्रीय औसत तक लाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती

8. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार के 20 फीसदी स्कूल एक या दो शिक्षकों के भरोसे'' के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रदेश के कुल 78,196 सरकारी विद्यालयों में से 3,276 प्राथमिक विद्यालय एक-एक एवं 12,507 विद्यालयों दो-दो शिक्षकों के भरोसे विद्यालय संचालित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रथम से बारहवीं कक्षा तक के सरकारी विद्यालयों में 3.15 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरकर छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

पटना :
दिनांक 30 नवम्बर,, 2021 (ई0) ।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

बि0स0मु0, 41(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550